अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

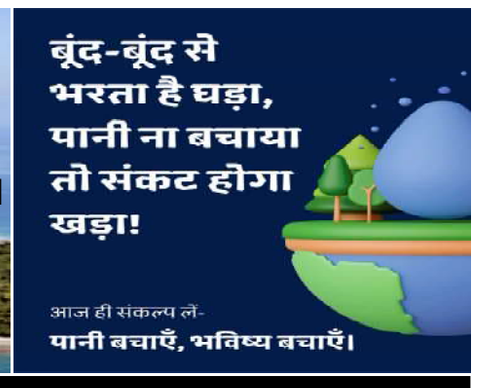

रजि.न.34300/80 संख्या 128 श्री विजय पुरम, शुक्रवार, 15 मई 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

रणनीतिक स्वायत्तता और भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल के निर्माण हेतु आत्मनिर्भरता एवं संयुक्तता अनिवार्य : माननीय रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 14 मई।

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु आत्मनिर्भरता एवं संयुक्तता को अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा, "किसी राष्ट्र की शक्ति तेजी से इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी सेनाएं, प्रयोगशालाएं और रक्षा उद्योग कितनी तत्परता से एकजुट होकर सोचते व कार्य करते हैं।" श्री राजनाथ सिंह 14 मई, 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कलम एंड कवच 3.0 रक्षा रणनीतिक संवाद के दौरान नीति–निर्माताओं, सैन्य नेतृत्व, रक्षा उद्योग के हितधारकों, राजनयिकों, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और रणनीतिक विशेषज्ञों को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

माननीय रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्धक्षेत्र में सफलता उन्हीं के हाथ लगेगी, जो किसी विचार, प्रोटोटाइप और उसके क्रियान्वयन के बीच के समयांतराल को न्यूनतम कर सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा भू–राजनीतिक तनाव, जारी संघर्षों, साइबर खतरों, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और हाइब्रिड युद्ध के उभरते स्वरूपों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अब पुराने अनुमानों पर आधारित नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारी तैयारी, लचीलापन, नवाचार और

रणनीतिक आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक हैं।" श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के लिए अत्यधिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, वह संकट के समय असुरक्षित हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, "हमें अपने राष्ट्रीय तंत्र के भीतर ही प्रमुख रक्षा प्रणालियों का डिजाइन, विकास, उत्पादन, रखरखाव और उन्नयन करना होगा। इसी के माध्यम से हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित कर सकेंगे।"

माननीय रक्षा मंत्री ने समन्वय और संयुक्तता की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि आधुनिक समय के

शेष पृष्ठ 4 पर

अण्डमान तथा निकोबार का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 81.08 प्रतिशत रहा

श्री विजय पुरम, 14 मई

अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (एआईएसएससीई) कक्षा 12वीं सत्र 2025–26 के परिणाम 13 मई, 2026 को घोषित किए गए।

सीबीएसई वेबसाइट से प्राप्त परिणामों के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी प्रबंधन विद्यालयों से कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल 4948 विद्यार्थियों में से 4012 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 524 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.08 प्रतिशत दर्ज़ किया गया है। वहीं, द्वीपसमूह के 10 विद्यालयों ने शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए हैं।

क्र.सं.	कक्षा 12वीं परीक्षा में शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालय
1.	केन्द्रीय विद्यालय संख्या–1
2.	जवाहर नवोदय विद्यालय, छोलदारी
3.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बंगाली
4.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लॉन्ग आइलैंड
5.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, टुसनाबाद
6.	विवेकानंद केंद्र विद्यालय, लंबा लाइन
7.	क्रिसेंट पब्लिक स्कूल
8.	एनसीएस, मिनी बे
9.	सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल
10.	सेंट ज़ेवियर स्कूल, मनारघाट

कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट कोर्ट 8 जून से

श्री विजय पुरम, 14 मई

रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज एवं न्यायमूर्ति रीतोब्रोतो कुमार मित्रा 8 जून, 2026 से 22 जून, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन/सुनवाई करेंगे।

सांसद ने द्वीपसमूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग उठाई

श्री विजय पुरम, 14 मई

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से आग्रह किया है कि द्वीपसमूह के विद्यार्थियों एवं आम जनता की शैक्षणिक आकांक्षाओं तथा भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित "डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी" मॉडल के स्थान पर संसद के अधिनियम के माध्यम से द्वीपसमूह में पूर्ण विकसित केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाए।

सांसद कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि माननीय सांसद ने आशा व्यक्त की है कि प्रशासन अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उच्च शिक्षा भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चाथम आरा मिल में 'आयुष्मान आरोग्य शिविर' संचालित

श्री विजय पुरम, 15 मई

क्षय रोग (टीबी) के प्रति जागरूकता, रोकथाम एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकारी आरा मिल, चाथम द्वारा अपने सम्मेलन कक्ष में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत ज़िला क्षय रोग अधिकारी, ज़िला टीबी केंद्र, दक्षिण अण्डमान के सहयोग से 'आयुष्मान आरोग्य शिविर' का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत क्षय रोग (टीबी) पर जागरूकता व्याख्यान से हुई, जिसमें रोग के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु शीघ्र पहचान, समय पर उपचार एवं बचाव संबंधी उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों के लिए रक्तचाप एवं रक्त शर्करा जांच सहित आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवाएं प्रदान की गईं तथा एक्स–रे जांच भी की गई। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह शिविर डॉ.

डेन्सी टोनी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। शिविर के सफल संचालन हेतु एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों की समर्पित टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर के दौरान कुल 48 एक्स–रे जांचें की गईं।

किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 14 मई

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा द्वीपसमूह में त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम–सेक्स सॉर्टेड सीमेन (एबीआईपी–एसएसएस) योजना को सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है, जो दुग्ध किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल सिद्ध हो रही है।

भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से मादा बछड़ों के जन्म की संभावना को काफी अधिक बढ़ाती है। यह उन्नत प्रजनन तकनीक किसानों को अपने दुग्ध पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ाने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता प्रदान कर रही है, साथ ही अवांछित नर बछड़ों के पालन–पोषण पर होने वाले खर्च को भी कम कर रही है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एबीआईपी–एसएसएस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 51 बछड़ों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 30 मादा बछड़े हैं। यह उत्साहजनक परिणाम इस तकनीक की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वर्तमान में उन्नत जर्सी क्रॉसब्रीड एवं साहीवाल नस्ल के जर्मप्लाज्म वाले सेक्स सॉर्टेड सीमेन की खुराकें सभी पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से किसानों को मात्र 250 रुपये प्रति खुराक की अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि किसानों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए योजना में कृत्रिम गर्भाधान असफल होने की स्थिति में

धनवापसी का प्रावधान भी शामिल है। वर्ष 2025–26 के दौरान ऐसे 26 किसानों को, जिनके पशु गर्भधारण नहीं कर सके, योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार धनवापसी प्रदान की गई। यह प्रशासन की पारदर्शिता एवं किसान कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने द्वीपसमूह के सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु आगे आकर एबीआईपी–एसएसएस योजना को सक्रिय रूप से अपनाएं। इस सेवा का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने निकटतम पशु चिकित्सालय अथवा औषधालय से संपर्क कर सकते हैं।

दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायक उपकरण मूल्यांकन शिविर लगाया गया

श्री विजय पुरम, 14 मई

दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के सहयोग से प्रधानमंत्री दिव्याशा व्योश्री केंद्र (पीएमडीवीके) पहल के अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से आज दक्षिण अण्डमान के फरारगंज स्थित अभ्युदय कॉम्प्लेक्स के दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम के निवासियों के लिए सहायक उपकरण मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान कुल 54 निवासियों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें 35 वरिष्ठ नागरिक एवं 19 दिव्यांगजन शामिल थे। सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विशेषज्ञों की बहु–विषयक टीम द्वारा लाभार्थियों की व्यक्तिगत कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत निरामया

स्वास्थ्य बीमा योजना तथा दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास संबंधी सेवाओं पर अभिमुखीकरण एवं जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए।

यह शिविर श्री अशोक बिस्वास, नोडल अधिकारी (दिव्यांगता), समाज कल्याण निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन तथा श्रीमती सुमिथामोल एस., निदेशक, सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आयोजित किया गया।

एमएसीपी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान

श्री विजय पुरम, 14 मई

कार्मिक विभाग द्वारा एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने हेतु समामेलित लिपिकीय संवर्ग कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1 ग्रुप 'बी' (राजपत्रित), 54 ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) तथा 7 ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है। उप सचिव (कार्मिक/भर्ती एवं परीक्षा/सीसी) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने से कर्मचारियों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे तथा उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

श्री विजया पुरम, 14 मई

सभी अभ्यर्थियों एवं आम जनता को सूचित किया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस में विभिन्न ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई, 2026 रात्रि 11.59 बजे (मध्यरात्रि) तक कर दी गई है।

अभ्यर्थी इस विस्तारित अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि पात्रता निर्धारण के लिए आयु गणना, वैध दस्तावेज़/प्रमाणपत्र/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की उपलब्धता के संदर्भ में कट–ऑफ तिथि 17 मई, 2026 ही रहेगी, जैसा कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अतः अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन जमा करने की बढ़ाई गई तिथि की परवाह किए बिना 17 मई, 2026 तक सभी पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हों। पात्रता संबंधी शर्तें एवं अन्य निर्देश विस्तृत भर्ती अधिसूचना में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, तो उसके लिए सुधार विंडो 28 मई, 2026 रात्रि 11.59 बजे (मध्यरात्रि) तक उपलब्ध रहेगी।

पुलिस अधीक्षक (भर्ती) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा प्रश्न के लिए अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भर्ती प्रकोष्ठ से **recruitment.phq@and.nic.in** ईमेल अथवा दूरभाष संख्या 03192–230735 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9.30 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 14 मई

अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी तथा रक्त केंद्र, जीबी पंत अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से श्री बाला सुब्रमणियम, समन्वयक/आयोजक, अण्डमान नोमाड्स क्लब एवं ड्रीम्ज निरवाना ट्रस्ट द्वारा 13 मई, 2026 को मनशा रीजेंसी, दिलानीपुर, श्री विजय पुरम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा कुल 30 यूनिट रक्तदान किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह शिविर डॉ. सुब्रत साहा, परियोजना निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी एवं निदेशक, राज्य रक्ताधान परिषद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का संचालन डॉ. डी. दिव्या, जूनियर रेजिडेंट, 'अनिम्स', जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम द्वारा किया गया। रक्तदाताओं की पात्रता की जांच की गई तथा उन्हें रक्तदान के विभिन्न पहलुओं एवं उसके महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। श्री बाला सुब्रमणियम, समन्वयक/आयोजक, अण्डमान नोमाड्स क्लब एवं ड्रीम्ज निरवाना ट्रस्ट, श्री विजय पुरम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा शिविर का आयोजन किया गया तथा शिविर के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। रक्त केंद्र, जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम और अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी की तकनीकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि संग्रहित रक्त इकाइयों की रक्तजनित संक्रामक रोगों के लिए जांच की जाए। साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं की पात्रता मानकों की भी जांच की। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रमाण–पत्र भी वितरित किए गए।

आईएमयू–सीईटी 2026 मेरिट सूची प्रदर्शित

श्री विजय पुरम, 14 मई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से स्नातक समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित आईएमयू–सीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 6 मई, 2026 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में किया गया था। इसके अनुसार आईएमयू–सीईटी 2026 के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची सभी संबंधित अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु 'डीब्राइट' के मेरीटाइम विंग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने विवरणों का सत्यापन कर लें तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आगामी सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए प्रशासन के संपर्क में बने रहें। 'डीब्राइट' द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी अपनी कक्षा 12वीं की अंक तालिकाओं की प्रतियां यथाशीघ्र मेरीटाइम विभाग अथवा प्राचार्य कार्यालय, 'डीब्राइट' में जमा करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), चेन्नई तथा प्रशासन को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु समय पर प्रेषित किए जा सकें।

कूडो अण्डमान टीम राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में करेगी भागीदारी

श्री विजय पुरम, 14 मई

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रेंशी धमैन तिर्की (कोच, कूडो अण्डमान) के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कूडो अण्डमान टीम 16 मई से 22 मई, 2026 तक पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली चौथी कूडो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कप 2026–27 में भाग लेगी। प्रतिभागियों में डॉन बॉस्को के अंश सरकार, सेंट मेरी स्कूल के शान अनीश अब्राहम, कार्मेल स्कूल की श्रेयाशी भट्टाचार्य, एनसीएस के दिवित भट्टाचार्य तथा रेंशी धमैन तिर्की शामिल हैं।

द्वीपों में भारी वर्षा के आसार

श्री विजय पुरम, 14 मई

आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 15, 16 एवं 18 मई को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के एक या दो स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा (7 से 20 सेंटीमीटर) होने की अत्यधिक संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज एवं झोंकेदार हवाओं के साथ आंधी तथा वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, 18 मई को द्वीपसमूह के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा (7 से 11 सेंटीमीटर) तथा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ गर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। अण्डमान तथा निकोबार तट तथा उससे सटे समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने तथा कभी–कभी इनके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

मछुआरों को 19 मई तक अण्डमान तथा निकोबार तट और उससे सटे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

रणनीतिक स्वायत्तता और भविष्य

—पृष्ठ 1 का शेष

युद्ध में अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, ''सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपनी रक्षा सेनाओं को थल, जल, वायु, साइबर और अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में कितने प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है।'' श्री सिंह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़त इस बात से तय होगी कि प्रयोगशालाएं, उद्योग, स्टार्टअप्स, नीति–निर्माता और सैन्य संस्थान कितनी निकटता व समन्वय के साथ मिलकर कार्य करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने अपने उद्घाटन संबोधन में 'कलम एंड कवच' के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ विचारों के संगम का मंच बताया। उन्होंने कहा कि कलम ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कवच संरक्षण, लचीलापन और राष्ट्र की सुरक्षा के दायित्व का प्रतीक है। रक्षा राज्य मंत्री ने युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के सुरक्षा खतरे पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं, जिनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दूरदर्शिता–आधारित तैयारी आवश्यक है। श्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार (जेएआई) के महत्व को दोहराते हुए कहा कि ये भारत की भावी सुरक्षा संरचना के केंद्रीय स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति संयुक्त सैन्य क्षमता, स्वदेशी विनिर्माण–आधारित नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से ही संभव होगी।

श्री संजय सेठ ने कहा कि भारत तकनीकी रूप से उन्नत, रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर उपस्थित विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि वैश्विक सुरक्षा एवं प्रगति सहयोग, विश्वास तथा साझा नवाचार के माध्यम से और अधिक सशक्त होती है। रक्षा राज्य मंत्री ने हालिया परिचालन उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को नए भारत की क्षमताओं का एक निर्णायक उदाहरण बताया। उन्होंने स्वदेशी प्रणालियों, त्वरित प्रतिक्रिया, तकनीकी एकीकरण और रक्षा बलों के बीच निर्बाध समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। श्री सेठ ने कहा कि ऐसे अभियान आतंकवाद के प्रति राष्ट्र की शून्य–सहिष्णुता नीति और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने के दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित करते हैं।

विज्ञान प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर शिविर हेतु चयन

श्री विजय पुरम, 14 मई

विद्यार्थी विज्ञान मंथन ने विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम के सहयोग से 21 दिसंबर, 2025 को कक्षा 6वीं से 11वीं तक के चयनित विद्यार्थियों हेतु राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया। इस राज्य स्तरीय शिविर में प्रत्येक कक्षा से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रत्येक कक्षा से प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 16 एवं 17 मई, 2026 को आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय शिविर में भाग लेने हेतु चयनित घोषित किया गया।

राष्ट्रीय स्तरीय शिविर हेतु चयनित विद्यार्थियों में कार्मेल स्कूल के कक्षा 6वीं लोहिताक्ष, विवेकानंद केंद्र विद्यालय के कक्षा 6वीं के हार्दिक चक्रवर्ती, नेवी चिल्ड्रेन स्कूल के कक्षा 7वीं के इशायु टॉकर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या–2 की कक्षा 7वीं की तनुश्री वशिष्ठा, सेंट मेरीज़ स्कूल, भातूबस्ती की कक्षा 8वीं की एस. समृद्धि, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल, ब्रुक्शाबाद के कक्षा 8वीं कक्षा के देवेश मजूमदार, नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की कक्षा 9वीं की बिदिशा मैती, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या–1 की 9वीं कक्षा की दिया आर. मेनन, विवेकानंद केंद्र विद्यालय की कक्षा 10वीं की एस. षणमुग प्रिया एवं वैभव गणपति तथा कार्मेल स्कूल की कक्षा 11वीं की अस्मिता एवं खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11वीं कक्षा की सुप्रिया यादव शामिल हैं।

विज्ञान केंद्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ये विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय शिविर (एनएलसी) में भाग लेने हेतु हमारे द्वीपसमूह से गुजरात प्रस्थान कर रहे हैं।

36 घंटे, एक छोटा–सा सुराग : हम्फ्रीगंज पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड हिट–एंड–रन मामला

श्री विजय पुरम, 14 मई

लगातार जांच, तीक्ष्ण तकनीकी विश्लेषण एवं समन्वित फिल्ड कार्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अण्डमान की हम्फ्रीगंज थाना की टीम ने घटना के मात्र 36 घंटे के भीतर एक ब्लाइंड हिट–एंड–रन मामले का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई में आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन को भी ज़ब्त कर लिया गया।

11 मई, 2026 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गाराचरामा से सीपीघाट के निकट काला पत्थर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। इसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज़ कर उप निरीक्षक गौरव बनर्जी, थाना प्रभारी हम्फ्रीगंज थाना, उप निरीक्षक अजिताभ कुमार दास, सहायक उप निरीक्षक अमल कुमार दास, हेड कांस्टेबल अरुल, होमगार्ड (नियमित) के. बालकृष्ण, एचजीवी बेनहर, ए. क्रिस्टोफर एवं जेरोम की एक पुलिस टीम तत्काल आरोपी का पता लगाने हेतु गठित की गई।

पुलिस टीम ने निरंतर प्रयास, समन्वित टीमवर्क, तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग, एलबीएस विश्लेषण तथा परिवहन विभाग नियंत्रण कक्ष के सहयोग से आरोपी की व्यापक तलाश शुरू की। विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध वाहन एवं उसके चालक का सफलतापूर्वक पता लगाया गया। पुलिस टीम तुरंत उक्त स्थान पर पहुंची, दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद किया तथा चालक की पहचान राज किशन, स्वर्गीय प्रेम किशन के पुत्र, आयु 24 वर्ष, पेशा निजी चालक एवं निवासी पत्थरगड्ढा के रूप में की। उसे गिरफ्तार कर विधिसम्मत औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद वाहन को ज़ब्त कर लिया गया।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह मामला उप निरीक्षक गौरव बनर्जी, थाना प्रभारी हम्फ्रीगंज थाना के मार्गदर्शन, श्री सुनील (दानिप्स), एसडीपीओ बम्बूफ्लाट के नेतृत्व तथा श्रीमती श्वेता के. सुगथन (आईपीएस), पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अण्डमान ज़िला के समग्र पर्यवेक्षण में सुलझाया गया।

आम जन से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अपराध अथवा अन्य अवैध गतिविधियों से संबंधित सूचना पुलिस को 112, 03192–232100 एवं 03192–236641 पर उपलब्ध कराएं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

940 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

श्री विजय पुरम, 14 मई

एंटी–नारकोटिक्स पुलिस थाना ने 12 मई, 2026 को यहां के जंगलीघाट स्थित पार्क के निकट चलाए गए अभियान के दौरान 940 ग्राम अवैध गांजा ज़ब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर एंटी–नारकोटिक्स पुलिस थाना की एक समर्पित पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व निरीक्षक के. बिनोज, थाना प्रभारी, एंटी–नारकोटिक्स पुलिस थाना कर रहे थे, ने ट्रॉली बैग लेकर जा रहे मणिरुल सरदार, पुत्र श्री ईमान अली सरदार, आयु 34 वर्ष, निजी श्रमिक एवं निवासी प्रेम नगर, विद्युत साइट कार्यालय के निकट, को रोका। उसके सामान की तलाशी लेने पर बैग के भीतर छिपाकर रखा गया 940 ग्राम गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए मादक पदार्थ को ज़ब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजीपी (सीआईडी) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मामले में शामिल आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने तथा अन्य सह–आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। यह छापेमारी श्रीमती सुमा मड्डा, उप पुलिस अधीक्षक (नारकोटिक्स) के पर्यवेक्षण में की गई।

डीजीपी कप लीग सह–नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट (सीज़न–1)–2026

श्री विजय पुरम, 14 मई

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा जेएनआरएम फुटबॉल स्टेडियम, श्री विजय पुरम में डीजीपी कप लीग सह–नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट (सीज़न–1)–2026 का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट मई, 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ होने वाला है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों तथा निजी युवा क्लबों की टीमों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक टीम के लिए प्रवेश शुल्क 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता में अधिकतम 30 टीमों को "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक (एपीयू) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक टीमें अधिक जानकारी हेतु आयोजन समिति के सदस्यों इंचार्ज स्पोर्ट्स एएसआई विजय शंकर–मोबाइल: 9531836010, श्री वी. हेंथो–मोबाइल: 9933263549, श्री केपी मम्मू–मोबाइल: 9474263519, श्री मोहम्मद मुस्तफा–मोबाइल: 9933297697, श्री नवीन कुजूर–मोबाइल: 8900924070 तथा श्री संभू मूर्ति–मोबाइल: 9679592298 से संपर्क कर सकती हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मई, 2026 सायं 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उपर्युक्त तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी टीम का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एमवी नालंदा की कोलकाता यात्रा के लिए अप्रयुक्त टिकटों का वितरण आज

श्री विजय पुरम, 14 मई

आगामी 16 मई, 2026 (शनिवार) को कोलकाता के लिए निर्धारित एमवी नालंदा के प्रस्थान हेतु आरक्षित कोटे में उपलब्ध अप्रयुक्त/समर्पित टिकट, यदि कोई हों, तो उन्हें कल 15 मई, 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 2 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। टिकटों की बुकिंग डीएसएस ई–टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त टिकट स्टार्स टिकट काउंटरों से भी खरीदे जा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ई–टिकटिंग पोर्टल से सीधे जुड़ने हेतु क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराया गया है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ग्राम पंचायत कार्यालय, रंगत, मध्य अण्डमान

ई–निविदा सूचना

No. 4-5/GP-RGT/MA/2026-27/322 दिनांक 13.05.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम की धारा 4 (2) के तहत परिभाषित रंगत ग्राम पंचायत के साधारण निवासियों से, ग्राम पंचायत रंगत के तहत दुकानों के आबंटन के लिए निविदा दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों पर, निविदा संख्या और नियत तारीख के साथ विधिवत मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा दस्तावेज (दुकान के विवरण, नियम और शर्तों और मूल्य बोली वाले तकनीकी बोली) नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान रु. 100/– (अप्रतिदेय) के भुगतान पर, प्रधान/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत रंगत को संबोधित एक मांग पत्र के साथ अंतिम तिथि से पहले प्राप्त किए जा सकते हैं।

तकनीकी बोली और मूल्य बोली (एक ही लिफाफे के अंदर रखे गए अलग–अलग लिफाफों में) वाले मुहरबंद निविदा को नीचे उल्लिखित अंतिम तिथि और समय से पहले ग्राम पंचायत रंगत कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में डालना होगा।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 08 जून, 2026 अपराहन 4.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 09 जून, 2026 के पूर्वाहन 11.00 बजे।

नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रधान
ग्राम पंचायत रंगत

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, हम्फ्रीगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्याः क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/जीईएन–आरजीपीएसए/2026–27/39

कार्य का नाम : हम्फ्रीगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड न. 01 में पंचायत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निकट 3 दुकानों का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 22,20,435/–, धरोहर राशि : रु. 44,409/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (08) आठ माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_23020_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, वी.के. पुर, लिटिल अण्डमान की ओर से, निम्नलिखित कार्यो के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/27

कार्य का नाम : लिटिल अण्डमान, वी.के. पुर, ग्राम पंचायत के अंर्तगत वी.के. पुर 07 में ब्लॉक रोड से सुधीर मंडल की जमीन तक ब्लैक टॉप रोड का निर्माण कार्य।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_23030_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

शपथ पत्र

मैं, मोहम्मद साहिल, पुत्र मोहम्मद शफी, निवासी ओग्राब्राज गाँव, फरारगंज तहसील, जिला दक्षिण अण्डमान, सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :–

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरे पिता का नाम मेरे 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में त्रुटिवश "मोहम्मद साफी" अंकित हो गया है, जबकि सही नाम "मोहम्मद शफी" है।
3. यह कि मेरे पिता का सही एवं वास्तविक नाम "मोहम्मद शफी" है।
4. यह कि "मोहम्मद साफी" तथा "मोहम्मद शफी" दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
5. मैं यह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि यह शपथ पत्र मेरे पिता के सही नाम "मोहम्मद शफी" को घोषित करने हेतु निष्पादित किया जा रहा है तथा आज की तिथि से उक्त सही नाम का ही उपयोग मेरे द्वारा सभी कार्यों एवं अभिलेखों में किया जाएगा।

यह कि उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

दिनांक : 13.05.2026
स्थान : श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग से जुड़े नए संशोधित नियम किए जारी

नई दिल्ली, 14 मई।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग (संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 3)' जारी कर दिए हैं। इन संशोधनों के तहत वर्ष 2016 के विनियमों में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक (एनबीसीएस), 2026 को शामिल किया गया है। साथ ही पुराने एनबीसी संदर्भों को एनबीसीएस से प्रतिस्थापित किया गया है।

ट्राई के अनुसार, ये विनियम उन संपत्ति प्रबंधकों पर लागू होंगे जो डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपनी संपत्तियों की रेटिंग या ऑडिट कराना चाहते हैं। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियां, इन–बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) प्रदाता और दूरसंचार सेवा प्रदाता भी इसके दायरे में आएंगे।

ये नियम उन सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होंगे, जो दूरसंचार सेवाएं देने के लिए संपत्तियों की डिजिटल संचार अवसंरचना और आईबीएस के साथ अपने नेटवर्क को एकीकृत करते हैं।

ट्राई ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों में स्पष्टता बढ़ाना, कार्यान्वयन को बेहतर बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही संपत्तियों में मजबूत, भविष्य के लिए तैयार और गैर–भेदभावपूर्ण डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। हालांकि, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग ढांचे के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को यथावत रखा गया है।

ट्राई ने बताया कि हितधारकों के साथ परामर्श और कार्यान्वयन के अनुभवों के आधार पर किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित रेटिंग मैनुअल भी उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

ट्राई के अनुसार, संशोधित नियम उसकी वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और ये 13 मई 2026 से प्रभावी हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (क्यूओएस–1) तेजपाल सिंह से संपर्क किया जा सकता है। ई–मेल: adv&qos1@trai-gov-in | फोन: 91–11–20907759 (इनपुट– पीआईबी)

संयुक्त सैन्य क्षमता मजबूत करने के लिए सेना और नौसेना में समझौता

नई दिल्ली, 14 मई।

देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने 'मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन अफिलिएशन' को मंजूरी दी है। गुरुवार 14 मई को दोनों सेनाओं के बीच 'संबद्धता समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य थलसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। बदलते युद्ध स्वरूप को देखते हुए इसे भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

सैन्य बलों के अनुसार यह समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता, एकीकरण और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप आधुनिक, एकीकृत और बहु–आयामी सैन्य क्षमता विकसित करना है। यह कदम देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच उत्कृष्ट तालमेल देखने को मिला था। सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों ने इस अभियान को उल्लेखनीय सफलता दिलाई। इस अभियान ने यह साबित किया कि भविष्य के सैन्य ऑपरेशन में संयुक्त और बहु–आयामी सैन्य संचालन कितने महत्वपूर्ण होंगे।

समझौते के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाने, परिचालन समन्वय मजबूत करने और दीर्घकालिक पेशेवर संबंध विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत सेना और नौसेना के अधिकारियों तथा जवानों को एक–दूसरे की कार्यप्रणाली, संचालन प्रणाली, प्रशिक्षण व्यवस्था और जिम्मेदारियों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

गुरुवार को हुए इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक और भारतीय नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ और नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन भी मौजूद रहे।

भारतीय नौसेना देश के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने और निर्बाध व्यापार संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं भारतीय सेना भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा, स्थिरता और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी निभाती है।

भविष्य के सैन्य अभियानों में तेजी से निर्णय लेने, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने और साझा संचालन क्षमता विकसित करने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसी कारण सेना और नौसेना के बीच मजबूत तालमेल और निर्बाध सहयोग को आवश्यक माना जा रहा है।

यह समझौता ज्ञापन भविष्य में भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बीच और अधिक अंतर–सेवा संबद्धताओं का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। साथ ही, यह संबद्ध गतिविधियों के संचालन के लिए व्यापक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराएगा, ताकि दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को संस्थागत रूप से और मजबूत बनाया जा सके। (इनपुट–आईएएनएस)

30 सितंबर 2026 तक सरकार ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 14 मई।

भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब उत्पादन में कमी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी की निर्यात नीति को 'Restricted' से बदलकर 'Prohibited' कर दिया है।

सरकार ने कहा है कि यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा Tariff Rate Quota व्यवस्था के तहत होने वाले निर्यात जारी रहेंगे। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत निर्यात भी मौजूदा विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और ब्राजील के बाद प्रमुख निर्यातकों में शामिल है। इससे पहले सरकार ने करीब 15.9 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी क्योंकि अनुमान था कि उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस फैसले से वैश्विक बाजार में कच्ची और सफेद चीनी की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। साथ ही एशिया और अफ्रीका के बाजारों में ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों के लिए निर्यात के नए अवसर भी बन सकते हैं।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गन्ना उत्पादन में सालाना आधार पर करीब 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जिससे चीनी और एथेनॉल उद्योग को समर्थन मिला है। हालांकि इसका लाभ मुख्य रूप से उन चीनी मिलों को मिला है जिनके पास एथेनॉल उत्पादन की एकीकृत क्षमता मौजूद है। (इनपुट–आईएएनएस)

अहमदाबाद में एचपीवी टीकाकरण अभियान ने हासिल किया 65 प्रतिशत लक्ष्य

नई दिल्ली, 14 मई।

अहमदाबाद नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत अहमदाबाद में 31 हजार से अधिक किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। नागरिक निकाय के अनुसार, 12 मई तक 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 31,579 किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी का टीका लगाया गया है।

अहमदाबाद नगर निगम ने इस अभियान के तहत कुल 48,443 पात्र किशोरियों की पहचान की है, जिनमें से अब तक लगभग 65 प्रतिशत को टीका लगाया जा चुका है। यह विशेष टीकाकरण अभियान 31 मई तक जारी रहेगा।

अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और समय पर टीकाकरण के जरिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने कहा कि पात्र किशोरियां शहर के किसी भी शहरी स्वास्थ्य केंद्र या नगर निगम संचालित अस्पताल में निःशुल्क टीका लगवा सकती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि निजी अस्पतालों में यह टीका लगभग तीन हजार रुपये का पड़ता है, जबकि नगर निगम इसे मुफ्त उपलब्ध करा रहा है। नगर निगम के अनुसार, यह अभियान गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि एचपीवी टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से सुरक्षा के सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। अभियान के तहत अधिक से अधिक पात्र किशोरियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरभर में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

तेल कंपनियों की एलपीजी डिलीवरी स्कैम को लेकर चेतावनी, जालसाज ओटीपी और ऑथेंटिकेशन के जरिए कर रहे फ्रॉड

नई दिल्ली, 14 मई।

सरकारी तेल कंपनियों ने देश में बढ़ रहे एलपीजी डिलीवरी स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि जालसाज गैस डिलीवर करने वाले वेंडर बनकर ओटीपी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया पर साइबर धोखाधड़ी के बारे में उपभोक्ताओं को आगह करते हुए कहा कि इस धोखाधड़ी में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को फर्जी एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, जो डिलीवरी नोटिफिकेशन की नकल करते हैं। इस मैसेज में ग्राहकों को वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) साझा करने के लिए कहा जाता है।

कई मामलों में, कॉल करने वालों ने गैस एजेंसी के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया और गैस कनेक्शन काटने से बचने के लिए केवाईसी अपडेट या आधार लिंक करने का अनुरोध किया, और फिर अनुरोधों को सत्यापित करने के लिए ओटीपी की मांग की है।

एचपीसीएल ने ग्राहकों को सूचित किया कि आधिकारिक डिलीवरी मैसेज 'वीएम–एचपीजीएएससी–एस' नाम से आएगा, जिसमें चार अंकों का ओटीपी होगा और इसका उपयोग केवल सिलेंडर डिलीवरी के समय किया जाएगा।

पोस्ट में कहा गया, एचपी गैस के प्रतिनिधि कभी भी फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश या संदिग्ध लिंक के माध्यम से ओटीपी नहीं मांगेंगे। साथ ही कहा, यदि संदेश अत्यावश्यक, अपरिचित या आधिकारिक प्रारूप से अलग

दिखता है, तो उस पर भरोसा न करें।

इसी तरह, इंडियन ऑयल ने ग्राहकों से आग्रह किया कि वे अपना 6 अंकों का डीएसी केवल इंडेन डिलीवरी कर्मियों के दरवाजे पर पहुंचने के बाद ही साझा करें। बीपीसीएल ने उपभोक्ताओं को कहा, केवल डिलीवरी के समय ओटीपी साझा करना ही उनकी सुरक्षा का एकमात्र नियम है।

इसके अलावा, तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे केवल इंडियनऑयल वन, एचपीपे या हेलो बीपीसीएल जैसे अपने आधिकारिक एप्लिकेशन के माध्यम से ही सिलेंडर बुक करें या विवरण अपडेट करें। सत्यापित वेबसाइटों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों से आने वाले मैसेज से सावधान रहना चाहिए।

अगर ग्राहक गलती से विवरण साझा कर देते हैं या उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, तो चोरी हुए धन को फ्रीज करने की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें गोल्डन आवर विंडो के भीतर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना चाहिए।–आईएएनएस

इतिहास के पन्नों में 15 मईः पर्वतारोहण में महिला का कमाल और मैकडॉनल्ड की शुरुआत का दिन

नई दिल्ली, 14 मई।

15 मई का दिन विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इस दिन पर्वतारोहण की दुनिया में एक महिला ने असाधारण उपलब्धि हासिल कर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचकर नया इतिहास रचा। इस साहसिक कारनामे ने महिलाओं की पर्वतारोहण क्षमता को लेकर बनी कई धारणाओं को बदल दिया।

उस महिला का नाम है एलिसन हारग्रीव्स। इस ब्रिटिश महिला पर्वतारोही ने बिना पूरक ऑक्सीजन और बिना किसी शेरपा की मदद के माउंट एवरेस्ट फतह किया था। उन्होंने यह असाधारण उपलब्धि 13 मई 1995 को हासिल की और इसके बाद 15 मई 1995 को दुनिया भर के मीडिया में इस खबर ने नया इतिहास रचा। पर्वतारोहण के इतिहास में इस उपलब्धि को आज भी प्रेरणादायक माना जाता है, जहां कठिन परिस्थितियों और कम ऑक्सीजन के बावजूद शिखर तक पहुंचना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। इस उपलब्धि ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को नई प्रेरणा दी।

इसी दिन वैश्विक फास्ट–फूड उद्योग की नींव भी रखी गई थी। 15 मई 1940 को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डीनो में रिचर्ड और मौरिस मैकडॉनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने एक छोटा सा रेस्तरां शुरू किया था। यही छोटा सा आउटलेट आगे चलकर वैश्विक फास्ट–फूड दिग्गज मैकडॉनल्ड में बदल गया।

आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के 100 से अधिक देशों में मौजूद है और इसके 35,000 से ज्यादा आउटलेट्स संचालित हो रहे हैं। बर्गर, फ्राइज और अन्य फास्ट–फूड आइटम्स के जरिए इस ब्रांड ने वैश्विक खाद्य संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इतिहासकारों के अनुसार, मैकडॉनल्ड्स की सफलता का बड़ा कारण इसका 'फास्ट सर्विस मॉडल' और मानकीकृत मेन्यू रहा, जिसने इसे दुनिया भर में तेजी से फैलने में मदद की।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1242– दिल्ली के सुलतान मुइजुद्दीन बहराम शाह की सेना ने विद्रोह कर दिया और सुलतान की हत्या कर दी।

1935– मास्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया।

1957– ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रशांत महासागर में किए गए श्रृखंलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था।

1958– सोवियत संघ ने स्पूतनिक–3 रॉकेट लांच किया।

1995– एलीसन गारग्रीब्स बिना आक्सीजन सिलीडंर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला बनीं।

1999– कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदत्त।

2001– इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत।

2002– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया।

2003– इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टामी फरैक्स के खिलाफ ब्रूसेल्स की अदालत में युद्ध सम्बन्धी मुकदमा दायर।

2005– 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा।

2008– श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबन्ध दो साल के लिए बढ़ाया।

2008– भारतीय मूल की मंजूला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनीं।

दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली, 14 मई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने और 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान जैसी कई घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में इससे संबंधित फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईंधन संकट और बढ़ती आयात लागत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू की जाएगी। निजी कंपनियों और संस्थानों को भी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी जा रही है। श्रम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो हेल्प डेस्क व कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।

एसआईआर के अगले चरण की घोषणा, देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा शुरू

नई दिल्ली, 14 मई।

भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत करने की घोषणा की। आयोग ने कहा कि यह एक बड़ा देशव्यापी अभियान होगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करना है।

आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम वर्तमान में जनगणना के तहत चल रहे मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया में लगी साझा फील्ड मशीनरी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। तीसरे चरण की शुरुआत के साथ एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं होंगे।

आयोग ने कहा कि इन तीन क्षेत्रों का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। यह निर्णय जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचाई वाले तथा बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस संशोधन अभियान के तहत 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) गणना चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर–घर जाकर सत्यापन करेंगे। इन बीएलओ की मदद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित लगभग 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) करेंगे।

ईसीआई ने एसआईआर को एक 'सहभागी और पारदर्शी प्रक्रिया' बताया है, जिसमें कई स्तरों पर मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी शामिल होते हैं। राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे संशोधन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए हर मतदान केंद्र पर

बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करें।

ज्ञानेश कुमार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर कहा, "मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे एसआईआर के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरें। एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाता ही शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम न रहे।"

आयोग ने आगे कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एसआईआर अभ्यास के पहले दो चरणों में संबंधित एसआईआर आदेश जारी होने की तारीख तक लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे। इसमें कहा गया है कि इन चरणों के दौरान प्रक्रिया के अलग–अलग स्तरों पर 6.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 9.2 लाख बूथ लेवल एजेंट को तैनात किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि इस गहन संशोधन अभियान का उद्देश्य डुप्लीकेट, स्थानांतरित, मृत या अयोग्य नामों की पहचान करके मतदाता सूची को सही और त्रुटि–मुक्त बनाना है। साथ ही सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना भी इसका लक्ष्य है।

डिजिटल पेंशन सुधारों ने पेंशन वितरण को बनाया सुगम और पारदर्शी–केन्द्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 14 मई।

केंद्रीय लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दशक में देश के पेंशन प्रशासन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब यह प्रक्रियाबद्ध प्रणाली से विकसित होकर प्रौद्योगिकी–सक्षम, जन–केंद्रित तंत्र बन गया है, जो पेंशनभोगियों की गरिमा, पारदर्शिता और जीवन सुगमता पर केंद्रित है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशनभोगियों को सरकारी सहायता लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदानकर्ताओं के रूप में देखना चाहिए, जिनका अनुभव, विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति राष्ट्रीय धरोहर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरल, सहानुभूति भरा और दायित्वपूर्ण पेंशन प्रशासन सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास किए हैं।

डॉ. सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी हितधारक साझा मंच पर बैठकर प्रायः मौके पर ही विवाद का सामूहिक समाधान करते हैं, बजाय इसके कि बातचीत केवल नियमित फाइल हस्तांतरण और आधिकारिक पत्राचार तक सीमित रहे।

वर्ष 2014 से पेंशन सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग लोगों की ध्यान से काफी हद तक बाहर रहते हुए सीमित प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निरंतर सुधारों, डिजिटल उपायों और नागरिक–केंद्रित निर्णय द्वारा यह सरकार के सबसे सक्रिय विभागों में से एक बन गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल

तकनीक द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने की सरकार की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान अब जन भागीदारी पहल में बदल गया है और इससे वृद्ध पेंशनभोगियों की कठिनाइयों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक पेंशनभोगी पहले ही इस प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं, जिससे पेंशन वितरण अधिक सुलभ, पारदर्शी और बाधा मुक्त हो गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री ने हाल के वर्षों में किए गए कई सुधारों का भी उल्लेख किया, जिनमें पारिवारिक पेंशन नियमों का सरलीकरण, गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित पुराने प्रावधानों को हटाना, तलाकशुदा और अलग हुई बेटियों से संबंधित प्रक्रियाओं में ढील और दिव्यांग आश्रितों के लाभ संबंधी सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार व्यावहारिक वास्तविकताओं और पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

भारत ने कहा– वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है

नई दिल्ली, 14 मई।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ० सुब्रह्मण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है– लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जनकेंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है।

इस अवसर विदेश मंत्री डॉ० एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इस जटिल और अनिश्चित दुनिया में चर्चाओं को समानता और साझा लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि तकनीकी प्रगति, वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन तथा समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने को लेकर भी साझा हित जुडे हैं।

डॉ० जयशंकर ने कहा कि भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंन कहा कि सभी सहभागी और सदस्य देश द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बातचीत के जरिये नियमित रूप से संपर्क में हैं। डॉ० जयशंकर ने कहा कि आज की बैठक अपने विचार साझा करने और विचारों पर सहमति विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगी।

डॉ० जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुडी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल

रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में चुनौतियों को सामना कर रहे हैं तथा ब्रिक्स संगठन इस स्थिति से और कारगर ढंग से निपटने में मदद कर सकता है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपने विचार साझा करने और सार्थक परिणाम में योगदान देने को कहा।

बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श करेंगे।

कल दूसरे दिन, ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स@20: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निमार्ण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक सितंबर–2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी।

झारखंडः भाव्य रंजन ने सीबीएसई 12वीं में 499 अंक हासिल कर रचा इतिहास

नई दिल्ली, 14 मई।

झारखंड की छात्रा भाव्य रंजन ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में कला विषयों में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। वे अखिल भारतीय टॉपर बनकर उभरी हैं। कोडरमा जिले के पाडी गांव की निवासी भाव्य ने अपनी इस उपलब्धि से पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता–पिता, शिक्षकों और अनुशासित अध्ययन दिनचर्या को दिया और आईएएस अधिकारी बनकर राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें एक बार फिर लड़कियों

ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों ने भाव्य को बधाई दी और उनकी इस उपलब्धि को झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताया।

आखिर क्यों जरूरी है परिवार का होना..? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस पर जानिए यूनाइटेड नेशन्स का बड़ा संदेश

नई दिल्ली, 14 मई।

हर वर्ष 15 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई–परिवार की भूमिका, चुनौतियों और बदलती परिस्थितियों पर गंभीर वैश्विक संवाद का अवसर बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस दुनिया भर में परिवारों के सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय मुद्दों को केंद्र में लाने का प्रयास करता है। वर्ष 2026 में यह दिन ऐसे समय पर मनाया जा रहा है, जब बढ़ती असमानताएं, आर्थिक दबाव और बदलती सामाजिक संरचनाएं परिवारों और बच्चों के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा की थी, ताकि परिवारों से जुड़े मुद्दों को वैश्विक स्तर पर पहचान और प्राथमिकता मिल सके। इसके बाद 1994 को "अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष" घोषित किया गया और 1995 से हर साल 15 मई को यह दिवस आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। समय के साथ इस दिवस का महत्व और भी बढ़ता गया, क्योंकि आधुनिक समाज में परिवारों के सामने नई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां लगातार उभरती रही हैं।

वर्ष 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम "Families, Inequalities and Child Wellbeing" रखी गई है। यह थीम इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ती असमानताएं किस प्रकार परिवारों की संरचना, जीवन स्तर और बच्चों

के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष विशेष रूप से बेहतर शिक्षा और बाल देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता, मजबूत सामाजिक सुरक्षा नीतियों, अभिभावकों के लिए सहयोग और भुगतान अवकाश जैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही बच्चों और परिवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने को भी वैश्विक प्राथमिकता बताया गया है।

दुनिया के विभिन्न देशों में इस अवसर पर परिवारों को केंद्र में रखकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं सामुदायिक सभाएं होती हैं तो कहीं स्कूलों और संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। परिवारिक एकता, सामाजिक समरसता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज को यह संदेश देना होता है कि मजबूत परिवार ही स्वस्थ और स्थिर समाज की नींव होते हैं।

नासा की बड़ी उपलब्धिः अंतरिक्ष में ही तैयार होगा IV फ्लूइड, लंबे मिशनों को मिलेगी नई ताकत

वॉशिंगटन, 14 मई।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक अहम तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। अब अंतरिक्ष में ही जरूरत के अनुसार इंट्रावेनस फ्लूइड तैयार किया जा सकेगा। यह तकनीक लंबे समय तक चलने वाले मानवयुक्त मिशनों, खासकर चंद्रमा और मंगल ग्रह की यात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

नासा हर मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन में जीवन रक्षक तरल पदार्थ की थैलियां अपने साथ ले जाता है। इसे आईवी या इंट्रावेनस द्रव कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और शुद्ध पानी का यह साधारण मिश्रण उड़ान के दौरान निर्जलीकरण, जलन और कई अन्य चिकित्सीय स्थितियों का इलाज कर सकता है। यह लगभग 30 प्रतिशत तक आम मेडिकल समस्याओं का उपचार करने में सक्षम है।

पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले मिशन तीन साल या उससे ज्यादा समय तक चल सकते हैं। ऐसे लंबे सफर में चालक दल के स्वास्थ्य के लिए IV द्रव की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन समस्या यह है कि पहले से पैक किए गए IV द्रव की शेल्फ लाइफ सिर्फ 16 महीने तक ही होती है। इतनी कम अवधि वाली आपूर्ति को स्टॉक करना जटिल और जोखिम भरा होता है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर (क्लीवलैंड) के वैज्ञानिकों ने एक उन्नत तकनीक विकसित की है। यह तकनीक अंतरिक्ष में उपलब्ध पानी को जरूरत के अनुसार चिकित्सा योग्य IV द्रव में बदल सकती है। अब टीम इस प्रणाली के छोटे और हल्के संस्करण का परीक्षण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर करने की तैयारी कर रही है।

इस परीक्षण के लिए आईवीजीईएन मिनी नामक सिस्टम नासा के नॉर्थ्रोप ग्रुम्मन कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज–24 (एनजी सीआरएस–24) मिशन के जरिए 11 अप्रैल को

अन्य सामान, प्रयोगों और हार्डवेयर के साथ स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया था। यह सिस्टम IV फ्लूइड बनाकर यह साबित करेगा कि डिजाइन अंतरिक्ष की परिस्थितियों में ठीक से काम करता है।

यह सिस्टम स्पेस स्टेशन के पीने वाले पानी को एक बड़े बैग में भरकर काम करता है। बैग को आईवीजीईएन मिनी से जोड़ा जाता है। सिस्टम पानी को अच्छी तरह छानकर उसमें मौजूद कणों और खनिज आयनों को पूरी तरह हटा देता है। फिर यह शुद्ध पानी एक बैग में जाता है, जिसमें पहले से तय मात्रा में सोडियम क्लोराइड भरा होता है। दोनों को सही अनुपात में मिलाने पर रोगाणु रहित और चिकित्सा के लिए सुरक्षित IV द्रव तैयार हो जाता है।

नासा ग्लेन की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर कर्टनी श्कुरको ने बताया कि लॉन्च के बाद मई में अस्थायी संचालन की योजना है। अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद दल दो दिनों तक इस सिस्टम को चलाएगा और लगभग 10 लीटर तरल पदार्थ तैयार करेगा। इसके बाद इस द्रव को पृथ्वी पर वापस लाकर उसकी जांच की जाएगी। जांच से पता चलेगा कि अंतरिक्ष में बने द्रव ने सभी जरूरी मानकों को पूरा किया है और इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

भारत का कौन–सा शहर कहलाता है "मिनी इंडिया"? जानिए क्यों मिली यह खास पहचान

नई दिल्ली, 14 मई।

भारत अपनी विविधता, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश के अलग–अलग राज्यों में अलग भाषा, पहनावा और खानपान देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जिसे "मिनी इंडिया" यानी "छोटा भारत" कहा जाता है?

यह सवाल इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन–सा शहर पूरे भारत की झलक एक साथ दिखाता है। अगर आप भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

भारत का दिल्ली शहर अक्सर "मिनी इंडिया" कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां रहने वाले अलग–अलग राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के लोग। दिल्ली में आपको लगभग हर राज्य के लोग मिल जाएंगे– पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, असम, महाराष्ट्र और उत्तर–पूर्व के राज्यों तक की संस्कृति यहां देखने को मिलती है। यही कारण है कि दिल्ली को "भारत की सांस्कृतिक राजधानी" और "Mini India" कहा जाता है।

दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण रोजगार, शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र है। यहां लाखों लोग दूसरे राज्यों से आकर बस चुके हैं।

दिल्ली की गलियों में आपको हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, भोजपुरी, मलयालम और कई अन्य भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी।

दिल्ली का फूड कल्चर पूरे देश में मशहूर है। यहां आपको– पंजाबी छोले भटूरे, दक्षिण भारतीय डोसा, बंगाली मिठाइयां, बिहारी लिट्टी–चोखा, राजस्थानी दाल–बाटी, नॉर्थ–ईस्ट मोमोज आदि सब कुछ एक ही शहर में मिल जाता है।

दिल्ली में त्योहारों की अलग ही रौनक होती है। दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस, छठ पूजा, पोंगल, बिहू, ओणम जैसे त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं।

दिल्ली की वो जगहें जहां दिखती है "पूरा भारत"

चांदनी चौक– पुरानी दिल्ली की पहचान, जहां अलग–अलग संस्कृतियों का अनोखा मेल दिखाई देता है।

कनॉट प्लेस– देशभर के लोगों का पसंदीदा व्यापारिक और पर्यटन केंद्र।

सरोजिनी नगर और लाजपत नगर– यहां अलग–अलग राज्यों के लोग और उनके फैशन का असर साफ दिखता है। देश के लगभग हर राज्य के खाने और मसाले यहां मिल जाते हैं।